



गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 159

दि. 08.10.2025,

बुधवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

ईमानदार अफसर की चुप्पी: हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की रहस्यमयी खुदकुशी से हिल गया पूरा सिस्टम

हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के उन चुनिंदा अफसरों में गिने जाने वाले वाई पूरन कुमार की खुदकुशी ने पूरे प्रशासनिक ढांचे और सियासी गलियारों में गहरा सदमा पहुँचा दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने सरकारी आवास में सोमवार को उन्होंने खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। यह खबर सामने आते ही हरियाणा पुलिस विभाग में सन्नाटा छा गया। उनके इस कदम ने न केवल एक सख्त और निडर अफसर की दुखद परिणति की कहानी कह दी, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि व्यवस्था के भीतर सच्चाई बोलना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना आज भी कितना भारी पड़ सकता है।



ने सिस्टम को खोखला बना दिया है। साल 2022 में उन्होंने नौ आईपीएस अधिकारियों पर दो-दो सरकारी आवास कब्जे में रखने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने बाकायदा शिकायत दी और सबूत भी पेश किए। उनकी शिकायत पर कार्रवाई हुई और संबंधित अधिकारियों से एक-एक आवास खाली कराया गया, साथ ही उनसे जुर्माना राशि भी वसूली गई। इस कार्रवाई ने विभाग के भीतर कई प्रभावशाली लोगों को असहज कर दिया। इसके बाद पूरन कुमार ने तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरोड़ा पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने पूर्व डीजीपी मनोज यादव के पक्ष में गलत रिपोर्ट दी है। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुँच गया। पूरन कुमार का टकराव केवल विभागीय स्तर पर ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने



राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव आयोग तक को चुनौती दी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में जाति के आधार पर अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति के अधिकारियों को हटया जा रहा है जबकि सवर्ण अधिकारियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। यह पहली बार था जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इतनी खुलेआम चुनावी प्रक्रिया में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी।

उनकी यह निर्भीकता कई लोगों को रास नहीं आई। बीते दिनों उनका ट्रांसफर रोहतक किया गया था, परंतु यह साफ

नहीं है कि उन्होंने नई पोस्टिंग ज्वाइन की थी या नहीं। बताया जाता है कि वे इस ट्रांसफर से काफी असंतुष्ट थे। इससे पहले 2024 में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को एक चिट्ठी लिखकर चार अधिकारियों की प्रमोशन को अवैध बताया था। उनका कहना था कि योग्यता और वरिष्ठता की अनदेखी कर राजनीतिक दबाव में पदोन्नति की जा रही है। उनके जीवन के अंतिम दिनों में वे अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास में रह रहे थे। उनकी पत्नी एक वरिष्ठ आईएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर थीं। जिस दिन यह घटना हुई, उस समय घर पर उनकी बेटी मौजूद थी। पूरन कुमार ने बेसमेंट में जाकर खुद को गोली मारी। चूँकि बेसमेंट पूरी तरह साउंडप्रूफ था, इसलिए किसी को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। जब काफी देर तक वे ऊपर नहीं आए तो परिवार ने नीचे जाकर देखा, जहाँ वे मृत पाए गए।

पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद होने की पुष्टि नहीं की है। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और परिवार से पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की,

अक्टूबर में मानसून की आखिरी दस्तक, सातव-भादो जैसी झमाझम बारिश से भीगा उत्तर भारत

निचली अदालतों में पदोन्नति की रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, अब संविधान पीठ तय करेगी न्यायिक अधिकारियों का भविष्य

नई दिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था में लंबे समय से चर्चा में रहे एक गंभीर मुद्दे — अधीनस्थ न्यायपालिका में पदोन्नति और करियर प्रगति की रुकावट — पर सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णायक रुख अपनाया है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया, ताकि इस संवेदनशील विषय पर एक व्यापक और स्थायी समाधान निकाला जा सके।

मुख्य न्यायाधीश जी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालतों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए वर्तमान पदोन्नति व्यवस्था न केवल सीमित है, बल्कि न्यायिक सेवा की प्रेरणा और गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि देशभर में अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, सेवा शर्तें और करियर प्रगति में भारी असमानता है, जिससे उनका मनोबल गिरता जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान चिंता व्यक्त की कि देश के कई हिस्सों में ऐसे युवा अधिकारी हैं जो 25 या 26 वर्ष की आयु में न्यायिक सेवा में प्रवेश करते हैं, परंतु पूरी सेवा के बाद भी अधिकतम अतिरिक्त जिला जज के पद से आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने कहा कि यह स्थिति स्वाभाविक रूप से हताशा और निराशा उत्पन्न करती है, जो न्यायपालिका के आत्मबल और दक्षता पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस मामले पर पहले जारी नोटिसों के जवाब में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से अलग-अलग विचार सामने आए हैं। कुछ राज्यों ने पदोन्नति प्रक्रिया को वरिष्ठता और योग्यता पर आधारित बताया, जबकि कई अन्य राज्यों में इसे सीमित पदों और कठोर मापदंडों की वजह से ठहरा हुआ माना गया। अदालत ने माना कि इन सभी मतभेदों को सुलझाने के लिए अब एक समान और संवैधानिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

संविधान पीठ यह तय करेगी कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा में पदोन्नति का किन किस प्रकार अधिक पारदर्शी और समान अवसर वाला बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि न्यायिक सेवा के विभिन्न स्तरों के बीच वेतनमान और करियर प्रगति में किस हद तक एकरूपता लाई जा सकती है, ताकि सभी राज्यों में न्यायपालिका में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न्यायिक सेवा में निचले स्तर पर काम कर रहे हजारों अधिकारियों को उम्मीदें जुड़ी हैं। दशकों से चली आ रही यह समस्या अब शायद किसी ठोस समाधान की दिशा में बढ़ेगी। अदालत का यह कदम केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की नींव को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है — ताकि न्याय देने वाले स्वयं भी अपने करियर में न्याय महसूस कर सकें।

नई दिल्ली। मानो इंद्रदेव ने अक्टूबर में एक बार फिर सावन-भादो का मौसम लौटा दिया हो। उत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में मंगलवार को आसमान से झमाझम बरसात हुई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक शाम ढलते ही काले बादलों ने आसमान को ढँक लिया और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। सोमवार को भी इंद्रदेव का यही प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन मंगलवार की बारिश ने तो मानो मानसून की विदाई को कुछ देर के लिए रोक दिया। दिल्ली में सुबह के समय आसमान पर काले बादल छा गए थे, फिर दोपहर में धूप खिली, लेकिन शाम चार बजे के आसपास फिर से मौसम पलट गया। पश्चिमी हवा के झोंकों के साथ अचानक तेज हवाएं चलीं और कई इलाकों में बिजली कड़कने लगी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों ने दोबारा झमाझम बारिश का आनंद लिया, लेकिन इससे ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी परेशानियाँ भी सामने आईं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मध्य दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम तक फैली हुई है। इसमें कुल 27 दिल्ली में भारी वर्षा हो सकती है। विभाग के अनुसार, यह बारिश कोई साधारण घटना नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र के पास सक्रिय है। इसकी वजह से चक्रवाती दबाव बन गया है, जिसके चलते बादल लगातार बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा: विकास तकनीक और कूटनीति की नई सौगातें

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जो देश में विकास, नवाचार और वैश्विक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस दौरान वे न केवल मुंबई मेट्रो लाइन-3 और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात कर भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगे।

प्रधानमंत्री मोदी मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण का शुभारंभ करेंगे। लगभग 37,270 करोड़ की लागत से बनी यह लाइन 33.5 किलोमीटर लंबी है और कफ परेड से आरे जेवीएलआर तक फैली हुई है। इसमें कुल 27 दिल्ली में भारी वर्षा हो सकती है। विभाग के अनुसार, यह बारिश कोई साधारण घटना नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र के पास सक्रिय है। इसकी वजह से चक्रवाती दबाव बन गया है, जिसके चलते बादल लगातार बने हुए हैं।



जबकि 12 किलोमीटर तक 20 और अधिकतम 50-60 के बीच। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र सरकार के STEP प्रोग्राम की भी शुरुआत करेंगे। यह योजना युवाओं को उद्योगों की आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए तैयार की गई है। इसमें 400 सरकारी ITI और 150 तकनीकी से लाखों यात्रियों को हर दिन सफर में बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इस मार्ग से रोजाना करीब 13 लाख लोग यात्रा करेंगे। किराया भी आम जनता के लिए किफायती रखा गया है — 3 किलोमीटर तक 10,

सोलर एनर्जी और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह पहल युवाओं को न केवल रोजगार दिलाने में मदद करेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। पीएम मोदी मुंबई वन मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे — यह भारत का पहला ऐस प्लेटफॉर्म होगा जो 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करेगा। इसमें मुंबई मेट्रो की सभी लाइनें, मोनोरेल, लोकल ट्रेन और BEST बस सेवाएं शामिल होंगी। यह ऐप यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग, रीयल टाइम

अपडेट्स और SOS सुरक्षा फीचर जैसी सुविधाएं देगा। इसके माध्यम से यात्रा न केवल आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 16,950 करोड़ की लागत से तैयार की गई यह हवाई अड्डा 1,160 हेक्टेयर में फैला है और भारत के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक बनने जा रहा है। इसके पहले चरण में टर्मिनल 1 और 3,700 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है, जो एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए सक्षम है। यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्रियों और 0.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में जब इसके सभी चार टर्मिनल पूरे हो जाएंगे, तब यह एयरपोर्ट हर साल 9 करोड़ यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने में सक्षम होगा। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत-ब्रिटेन “विजन 2035” रोडमैप की प्रगति की समीक्षा करेंगे,

जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा होगी। साथ ही वे भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर भी बातचीत करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों देश आने वाले दशक में निवेश, तकनीकी सहयोग और नवाचार के नए अवसरों की दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 6वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी हिस्सा लेंगे, जहां दोनों नेता डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय नवाचार पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह महाराष्ट्र दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है — यह भारत के तकनीकी, आर्थिक और कूटनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला अध्याय है। मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक, और युवाओं के कौशल विकास से लेकर वैश्विक साझेदारी तक, यह दौरा भारत के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और वैश्विक नेतृत्व वाले युग की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है।



संपादकीय

शांति की आस

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की तीव्र आकांक्षा के बीच की कई पहल से गाजा में दो साल से जारी इस्त्राइल के निरंकुश हमलों पर रोक लगने की आस जगी है। मिस्र के शर्म अल-शेख रिसॉर्ट में अमेरिका की मध्यस्थता में शुरू हुई वार्ता ने दुनियाभर में भरोसा जगाया है कि अब गाजा संकट का समाधान निकल सकता है। वास्तव में दो साल से जारी इस्त्राइल-हमास संघर्ष में मानवता कराह रही है। हालांकि, इस संकट की शुरुआत हमास के क्रूर आतंकी हमले से ही हुई थी। दरअसल, यह संघर्ष 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के आतंकवादियों द्वारा इस्त्राइल की धरती पर गए स्तब्धकारी क्रूर हमले के बाद शुरू हुआ था। इस जघन्य नरसंहार में इस्त्राइल व कुछ अन्य देशों के बारह सौ के करीब नागरिक मारे गए थे। इतना ही नहीं हमास के आतंकवादी 250 इस्त्राइली व अन्य देशों के लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे ताकि इस्त्राइल पर वार्ता में दबाव बनाया जा सके। अभी कुछ जीवित बंधक तथा कुछ मृतकों के शव हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें वह वार्ता में ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा है। इस घटनाक्रम को यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार के बाद दूसरा बड़ा खूनी दिन बताया गया था। जिसका जवाब इस्त्राइल ने गाजा को मरिट्यामेट करके दिया, जिसमें हमास के आतंकवादियों समेत 67000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। जिसमें अधिकांश आम नागरिक थे। इस्त्राइल के लगातार जारी घातक हमलों से गाजा आज खराबतर में तब्दील हो गया है। बताया जाता है कि करीब 22 लाख गाजावासियों में ज्यादातर बेघर हैं और भूख से जूझ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र वरिष्ठ जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला था कि गाजा में इस्त्राइली हमलों की कार्रवाई नरसंहार की श्रेणी में आती है। मिस्र के शर्म अल-शेख रिसॉर्ट में अमेरिका की मध्यस्थता में शुरू हुई वार्ता के बाद कहा जा रहा है कि इस्त्राइल और हमास अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय योजना के कुछ हिस्सों को लेकर सहमत हो गए हैं। बहरहाल, इस्त्राइल व हमास के समझौते की ओर बढ़ने से हमास के कब्जे में रखे गए बंधकों की रिहाई की उम्मीद भी जगी है। हालांकि, इस समझौता वार्ता का एक विवादस्पद मुद्दा हमास का निरस्त्रीकरण भी है, जिसे हमास स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहा था। वहीं गाजा के शासन से हमास को बाहर रखे जाने के मुद्दे का भी वार्ता के परिणामों पर प्रतिकूल अंतर पड़ सकता है। इस वार्ता को लेकर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भारत ने ट्रंप की योजना को फलस्तीन और इस्त्राइली लोगों के लिये दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग बताते हुए, इस पहल की सराहना की है। निस्संदेह, भारत की यह सक्रिय प्रतिक्रिया हाल के वर्षों में गाजा संघर्ष में युद्धविराम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से उसके बार-बार परहेज करने के बिल्कुल विपरीत है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही भारत ने फलस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य विकल्प के क्रियान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ सितंबर को कतर पर हुए इस्त्राइली हमलों की निंदा की थी। हालांकि, उन्होंने इस बाबत हमलावर, इस्त्राइल का नाम लेने से परहेज किया था। इसमें दो राय नहीं कि ट्रंप की योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन देना स्पष्ट रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों को पटरी पर लाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली ने इस्त्राइल के मामले में काफी हद तक सावधानी बरती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि फलगाम हमले के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के बचाव के अधिकार का इस्त्राइल ने पुरजोर समर्थन किया था। भारत को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में उसकी यह पहल अशांत क्षेत्र में शांति बहाल होने पर फायदेमंद साबित हो सकती है।

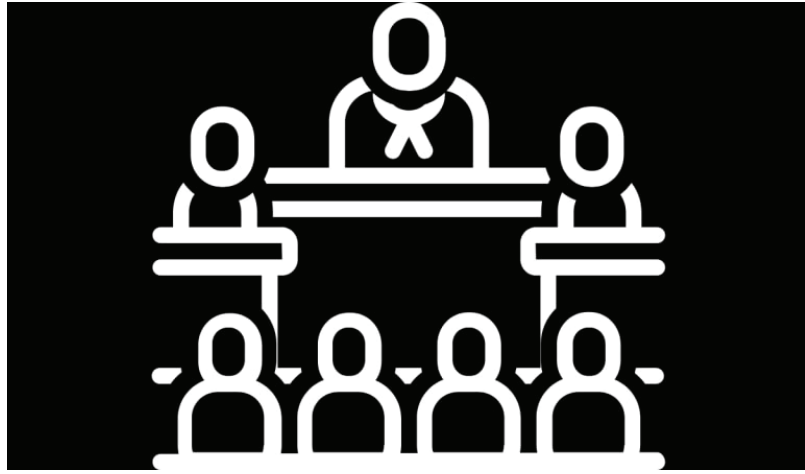
ताकि दवा जहर बन फिर से मासूमों की मौत न बने

दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच इन दो प्रमुख राज्यों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक एवं त्रासदीपूर्ण है।

प्रेरणा



अडिग विश्वास की शक्ति



मार्टिन लूथर किंग का जीवन इस बात का साक्षात उदाहरण है कि जब किसी मनुष्य के भीतर विश्वास की लौ प्रज्वलित हो जाती है, तो कोई भी अन्याय, कोई भी अत्याचार उसे झुका नहीं सकता। वे उस समय जन्मे थे जब अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ गोरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। रंग के कारण मनुष्य की पहचान तय होती थी, और यह भेदभाव इतना गहरा था कि काले लोगों को बसों में पीछे बैठने, होटलों में अलग हिस्सों में रहने और स्कूलों में अलग पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। समाज में यह असमानता इतनी सामान्य हो चुकी थी कि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कभी यह व्यवस्था बदलेगी। बचपन से ही मार्टिन ने देखा कि उनके अपने माता-पिता और समाज के लोग गोरों के अपमान को सहते रहते हैं। एक बार वे अपने एक गारे मित्र के साथ खेल रहे थे, तो उसके पिता ने उन्हें डांटकर दूर कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी अश्वेत के साथ खेले। यह घटना बालक मार्टिन के मन में गहरे उतर गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह केवल उनके साथ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के साथ अन्याय है। यही क्षण था जब उनके भीतर क्रांति का बीज अंकुरित हुआ।

जैसे-जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने समाज में व्याप्त इस अन्याय को मिटाने का प्रण लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को अपनाया। उन्हें विश्वास था कि हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और सत्य से ही दुनिया बदली जा सकती है। उन्होंने कहा था कि “अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रकाश ही समाप्त कर सकता है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रेम ही मिटा सकता है।” यह उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की। पहले तो लोग उन पर हँसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें पागल कहते थे। लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने कहा, “जब पूरी सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती, तब भी विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाओ।” यही उनका जीवन दर्शन था। धीरे-धीरे लोगों ने उनकी बातों में सच्चाई देखी। हजारों लोग उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा किए भी क्रांति लाई जा सकती है। उनके “आई हैव अ ड्रीम” भाषण ने मानव इतिहास में एक नई चेतना जाग दी। उन्होंने कहा कि उनका सपना है — “एक दिन यह देश अपने सच्चे आदर्शों पर खरा उतरेगा, और सभी मनुष्य समान अधिकारों के साथ जिंएंगे।” यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि मानवता के भविष्य की पुकार थी।

को अपनाया। उन्हें विश्वास था कि हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और सत्य से ही दुनिया बदली जा सकती है। उन्होंने कहा था कि “अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रकाश ही समाप्त कर सकता है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रेम ही मिटा सकता है।” यह उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की। पहले तो लोग उन पर हँसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें पागल कहते थे। लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने कहा, “जब पूरी सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती, तब भी विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाओ।” यही उनका जीवन दर्शन था। धीरे-धीरे लोगों ने उनकी बातों में सच्चाई देखी। हजारों लोग उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा किए भी क्रांति लाई जा सकती है। उनके “आई हैव अ ड्रीम” भाषण ने मानव इतिहास में एक नई चेतना जाग दी। उन्होंने कहा कि उनका सपना है — “एक दिन यह देश अपने सच्चे आदर्शों पर खरा उतरेगा, और सभी मनुष्य समान अधिकारों के साथ जिंएंगे।” यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि मानवता के भविष्य की पुकार थी।



दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर ऑथॉरिटी ने कई राज्यों में जांच की है। इन घटनाओं से साफ है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर लापरवाही व्याप्त है। कई कंपनियाँ लागत घटाने के लिए औद्योगिक ग्रेड के सॉल्वेंट या रसायनों का प्रयोग कर लेती हैं जो मानव उपभोग के लिए निषिद्ध होते हैं। वहीं निरीक्षण और परीक्षण की सरकारी व्यवस्था न केवल कमजोर है बल्कि अक्सर प्रभावशाली कंपनियों के दबाव में निष्क्रिय भी हो जाती है। राज्य और केंद्र स्तर के दवा-नियामक विभागों में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिससे समय पर निगरानी और सैपल परीक्षण संभव नहीं हो पाता। जब निरीक्षण औपचारिकता बन जाए और रिपोर्ट खरीद-फरोख्त की वस्तु बन जाएं, तब ऐसी त्रासदियाँ स्वाभाविक हैं। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के ‘कोल्ड्रुफ’ कफ सिरप के नमूने में 48.6 प्रतिशत डाई एंथिलीन ग्लाइकोल मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल

गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई। इसे भी पढ़ें: कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें चिंताजनक, दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखना सबसे बड़ी जरूरत इन घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी धब्बा लगाया है। पिछले वर्षों में अफ्रीकी देशों में भी भारतीय सिरप से हुई मौतों के बाद कई देशों ने हमारे फार्मा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। अब फरेलु स्तर पर घटित ऐसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि हमने उन हार्दसों से कोई सबक नहीं लिया। दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादक देश के रूप में भारत को यह मानना होगा कि केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। इस संकट का सबसे पीड़ादायक पहलु यह है कि इसका शिकार वे मासूम बच्चे बने जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी और जिनकी जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व समाज और राज्य पर है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी केवल दोषी कंपनियों पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर है जिसने नियमन और नैतिकता की आंखें मूंद

लीं। दवाओं में मिलावट या गलत प्रमाणपत्र देना कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। इस पर कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सो बार सोचे। भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझौली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद अफिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हार्दसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इम्पेक्टरो की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

इसके साथ ही चिकित्सा जगत और समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टरों को यह समझना होगा कि शिशुओं को ओटीसी- ऑवर

दी कॉउन्टर दवाएं देना कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार द्वारा जारी परामर्श और चेतावनियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सो बार सोचे। भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझौली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद अफिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हार्दसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इम्पेक्टरो की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। इसके साथ ही चिकित्सा जगत और समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टरों को यह समझना होगा कि शिशुओं को ओटीसी- ऑवर

प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्षों का सफर

सिर्फ सत्ता में बने रहने की नहीं बल्कि संकल्प से सिद्धि की कहानी है

7 अक्टूबर 2001, यह वह दिन था जब गुजरात विधानसभा के प्रांगण में एक साधारण स्वयंसेवक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर वहीं से प्रारंभ हुआ जो आज 25 वर्ष बाद भारतीय राजनीति के सबसे निर्णायक, सबसे प्रभावशाली नेतृत्व की कहानी बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अपने सोशल मीडिया संदेश में न केवल अतीत को याद किया, बल्कि “विकसित भारत” के अपने सपने को दोहराया। उन्होंने लिखा— “जनता के आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में सेवा के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। मेरा हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए रहा है।”

देखा जाये तो 2001 में गुजरात का नेतृत्व संभालने वाले मोदी ने उस राज्य को उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधारों का मॉडल बनाया। 2002 के बाद गुजरात ने जिस तीव्र गति से विकास किया, उसने पूरे देश में “गुजरात मॉडल” की चर्चा शुरू की। बिजली, जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन और निवेश में राज्य ने नए आयाम स्थापित किए। यही मॉडल आगे चलकर 2014 में नरेंद्र मोदी को देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी तक लेकर आया।

जब उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश आर्थिक ठहराव, भ्रष्टाचार और वैश्विक अविरवास से घिरा था। मोदी ने इस ठहराव को तोड़ते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र के साथ नई ऊर्जा भरी। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी आत्मविश्वास की नई परिभाषा गढ़ी।

प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्षों का यह सफर सिर्फ सत्ता में बने रहने के कहानी नहीं है; यह संकल्प से सिद्धि की कहानी है। पिछले दशक में भारत ने अनेक ऐतिहासिक परिवर्तन देखे। डिजिटल इंडिया ने शासन और नागरिकों के बीच पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की। स्वच्छ भारत मिशन ने सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। उज्ज्वला योजना से करोड़ों गरीब परिवारों की रसोई में धुआंमुक्त जीवन पहुंचा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने अर्थव्यवस्था को नवाचार और आत्मविश्वास की दिशा दी। चंद्रयान-3 और गगनयान मिशन ने विज्ञान में भारत की साज को

नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विश्व बैंक, IMF, तथा विश्व आर्थिक मंच तक इसे “ग्लोबल ब्राइट स्पॉट” कह रहे हैं। इसके अलावा, मोदी युग की एक सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि भारत की आक्रामक लेकिन संतुलित विदेश नीति रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को नई प्रतिष्ठा दिलाई। G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी ने भारत को ‘विश्व के विश्वास’ के केंद्र में ला खड़ा किया। इंडो-पैसिफिक एग्रीनौति और क्वाड गठबंधन में भारत की भूमिका अब निर्णायक है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी का “यह युद्ध का युग नहीं है” वाला संदेश आज वैश्विक कूटनीति की मिसाल बन चुका है। इसके अलावा, अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया में भारत ने न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को भी मजबूत किया है। मोदी की विदेश नीति की खासियत यह है कि उन्होंने ‘वसुधैव कुटुम्बक’ के दर्शन को आधुनिक कूटनीति में ढाल दिया— जहां भारत न किसी के सामने झुकता है, न किसी को झुकता है।

आज, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में अपनी माँ की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा— “उन्होंने कहा था, दो बातें कभी मत भूलना— गरीबों के लिए काम करना और कभी रिश्तत मत लेना।” यही मूल्य आज उनके राजनीतिक जीवन की धुरी हैं। उनकी ‘गरीब कल्याण’ नीतियों से लेकर ‘न्यू इंडिया’ की दृष्टि तक— हर कदम जनता के सशक्तिकरण की दिशा में रहा है। आज मोदी 25 वर्षों के इस सार्वजनिक जीवन में उस दौर के नेता हैं जिन्होंने न केवल सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, बल्कि भारतीय राजनीति में ‘गवर्नेंस का धर्म’ स्थापित किया। देखा जाये तो 25 वर्षों की यात्रा में नरेंद्र मोदी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन चुके हैं— आत्मनिर्भरता, राष्ट्रप्रेम और जनता के सशक्तिकरण का विचार। उनकी प्रतिबद्धता, वैश्विक दृष्टि और अडिग राष्ट्रवाद ने भारत को एक ऐसी राह पर डाल दिया है जहाँ ‘विकसित भारत’ अब सपना नहीं, लक्ष्य बन चुका है। जैसे-जैसे 2047 की ओर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश और प्रासंगिक हो उठता है— “सेवा ही सम्मान है, और भारत का उत्थान ही मेरा धर्म।”

